IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभावः एक अध्ययन

Pratima Shukla[1] and Dr. Hari Om Agrawal[2]

Research Scholar, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh, India[1]

Professor, Department of Commerce, Government (Autonomous) P.G College, Satna, Madhya Pradesh, India[2]

सारांशः

भारत के प्रधान मंत्री ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की और इस दिन देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

पहला विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किया गया था, जबकि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासित किया गया था।

उस समय सरकार द्वारा कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों की जाँच के लिए 10 पाउंड के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।

विमुद्रीकरण का दूसरा निर्णय स्वतंत्रता के बाद 16 जनवरी 1978 को किया गया था। रुपये के नोटों यानी रुपये के नोटों को विमुद्रीकृत करने का निर्णय लिया गया था जिसमे 1000, 5000 और 10000 के नोटो को बंद किया गया था।

लेकिन पिछले 2016 के विमुद्रीकरण से इस तरह अलग हैं कि पिछले दो मौकों पर प्रतिबंधित मुद्रा को एक नए नियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था

भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास

विमुद्रीकरण हमारे भारत देश के लिए नया नहीं था। हमारे देश में पहली बार 1946 में 500, 1000 और 10 हजार के नोट बंद करने का फैसला लिया गया था।

फिर 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर जांच पर वांचू समिति ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन यह सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके कारण विमुद्रीकरण हुआ।

जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। हालांकि आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर आईजी पटेल ने नोटबंदी का विरोध किया था।

भारत में 2005 में, मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार ने 2005 से पहले 500 के नोटों को बंद कर दिया था। 2016 में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला किया।

इन दो मुद्राओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया। इन नोटों का बाजार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। इस कारण से इसने इतना बड़ा विकार और परिणाम उत्पन्न किया

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

भारत में विमुद्रीकरण के प्रभाव

1.कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि जीडीपी को कम करके, विमुद्रीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, क्योंकि कई छोटे और मध्यम उद्यमों ने नकदी की कमी के कारण अपने व्यवसाय बंद कर दिए हैं।

नोटबंदी के दौरान गरीबों के जनधन खातों समेत बैंक खातों में कुल 15.28 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए। जन धन खातों में धन कर चोरों द्वारा जमा किया गया था, जिन्होंने अपना धन खोने से बचने के लिए ऐसा किया था।

यह राशि जो अब तक लॉकरों में बेकार पड़ी थी तुरंत कर योग्य हो गई जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। विमुद्रीकरण ने नकली नोटों के चलन को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। नोटबंदी के बाद नकली नोटों की संख्या कम से कम 0.0035: थी।

2.विमुद्रीकरण एक ऐसा निर्णय था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अल्पकालिक असुविधाएँ दी लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ थे। अल्पकालिक असुविधाओं में नकदी की कमी, बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारें शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक लाभ कम हो जाएंगे दृ जिससे भ्रष्टाचार–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी गतिविधियाँ, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अधिक बचत, अंततः सकल घरेलू उत्पाद में कमी आएगी।

3.विमुद्रीकरण के बाद आयकर रिटर्न 43.3 मिलियन से बढ़कर 52.9 मिलियन हो गया। विमुद्रीकरण के प्रमुख प्रभावों में से एक यह था कि इसने भारत में डिजिटल भुगतान के प्रयास के प्रयास को बढ़ावा दिया।

लंबी–लंबी कतारें लगीं और नकदी की कमी के कारण लोगों ने डिजिटल तकनीक को अपनाना ही बेहतर समझा।

इसने भ्रष्टाचार के लिए स्पीड ब्रेकर के रूप में भी काम किया। भ्रष्टाचार संयोजकों के बीच धन के अवैध आदान–प्रदान के कारण सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया।

विमुद्रीकरण से हानि

स्थानीय धन की कमी के कारण पर्यटन स्थलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। कई लोगों ने अपना भारत दौरा रद्द भी कर दिया। काम में मंदी आ गई थी।

आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में एक समस्या उत्पन्न हुई। घंटों बैंकों और एटीएम के सामने खड़े रहने से अस्पताल के बिलों, बिजली के बिलों, किराये की समस्याओं और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

आज के समय में नोटबंदी पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विमुद्रीकरण विफल हो गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें काले धन को सफेद किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 से घटकर 6.3 रह गई है।

नए नोट छापने में काफी पैसा खर्च हुआ लेकिन आतंकी फंडिंग अभी भी जारी है। हम उन आरोपों से बच भी नहीं सकते, शायद नोटबंदी से जिस स्तर की उम्मीद थी वह हासिल नहीं हुआ।

निष्कर्ष:

विमुद्रीकरण के निर्णय से आम लोगों को असुविधा हुई होगी, निश्चित रूप से इसके मूल में राष्ट्रीय हित और आर्थिक विकास था। भारत दशकों से भाग्यवाद और आतंकवादी गतिविधियों के अधीन रहा है।

विमुद्रीकरण एक निश्चित अवधि के लिए देश के हितों को खतरे में डाला है साथ ही साथ काले धन की समस्याओं पर हमला किया है और वित्तपोषण को नाकबंद किया है।

अब यह सुनिश्चित हो गया है कि इनमें से अधिकांश समस्याएं समाप्त हो गई हैं और भविष्य में इन समस्याओं के कारण भारत की विकास दर में कोई कमी नहीं आएगी, यानी हमारा देश तेजी से विकास करेगा।

विमुद्रीकरण ने कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जबकि विमुद्रीकरण के कई सकारात्मक अल्पकालिक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। सतह पर विमुद्रीकरण के प्रभावों को आने में पांच से छह साल लगेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. योजना पत्रिका जनवरी 2019
2. कुरूक्षेत्र पत्रिका मार्च 2018
3. दैनिक समाचार पत्र